राइट टु सर्विस कमीशन, सरकारी दफ्तर और टीसी गुप्ता..

जैसा नाम-वैसा काम। टीसी गुप्ता पर यही कहावत फिट बैठती है। जहां जाते हैं, वहीं से खड़े होकर अपनी लकीर खींचना शुरू कर देते हैं। फाइलों को बारीकी से पढ़ने वाले, अपना प्वाइंट ऑफ व्यू फाइल पर स्पष्ट लिखने में माहिर टीसी गुप्ता ने राइट टु सर्विस कमीशन में चीफ कमिश्नर का पद संभालते ही यह जताना शुरू कर दिया है कि हरियाणा में सेवा का अधिकार आयोग नाम की एक संस्था भी है। कांग्रेस काल में रिटायर्ड चीफ सेक्रेट्री एससी चौधरी इस कमीशन के चीफ कमिश्नर बने थे। तब आयुक्त भी लगाए गए थे। मगर हरियाणा सरकार के अफसरों को पता ही नहीं चला कि कोई आयोग बना भी था या नहीं। एक अफसर ने तो यहां लिख दिया कि आयोग में काम न के बराबर है। मगर टीसी गुप्ता ने पदभार संभालते ही आयोग की गरिमा बढ़ाने के लिए पहला कदम उठाते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चार एस्टेट अफसरों को तलब करते हुए पूरा रिकॉर्ड मंगा लिया कि एक जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक सेवाएं लेने के लिए कितने आवेदन आए, कितने समय में निपटाए गए, कितने में देरी हुई? गुप्ता ने अधिनियम के अनुरूप स्वयं संज्ञान लिया। गुप्ता ने एक और काम किया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रह चुकीं और वर्तमान में एचसीएस अफसर मीनाक्षी राज को राइट टु सर्विस कमीशन में सचिव तैनात करवा लिया। गलियारे में चर्चा है कि हरियाणा सरकार के जिन विभागों की 500 सेवाएं ऑनलाइन हैं, उन्हें अब कमर कसनी होगी। अन्यथा चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता की नजरों से बच नहीं पाएंगे।